अध्ययन सामग्री निर्माण
Dr. SHAKEEL HUSAIN
Head . Dept. of Political Science
Govt. VYT.PG Autonomous College
Durg CG.
shakeelvns27@gmail.com

E GOVERNANCE

ई गवर्नेन्स

अवधारणा

कंप्यूटर और इंटरनेट ने मानवीय जीवन पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला है । उसने सूचनाओ के आवागमन को इतनी अधिक गति दी कि इसे सूचना क्रांति कहा जाने लगा ।
ई गवर्नेंस ऐसी सूचना क्रांति का एक हिस्सा है ।
1990 का दशक इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 1990 के दशक के बाद की दुनिया एक नई दुनिया है । जिसे अनेक कारण है जिसमें दो प्रमुख हैं

- शीत युद्ध की समाप्ति - सोवियत संघ की समाप्ति के साथ शीत युद्ध की समाप्ति और एक नए आर्थिक रूप से प्रतियोगी विश्व का उदय ।
- वैश्विकरण - मुक्त बाजार वाले प्रतियोगी विश्व हेतु नई आर्थिक संरचनाओं का जन्म जिसे हम ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं जिसमें विश्व व्यापार संगठन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

1990 के दशक के बाद भारत में भी उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था से हम धीरे-धीरे प्रतियोगी और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर रहें आवश्यक तत्व है ग्राहकों की संतुष्टि इसका असर प्रशासनिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है । प्रशासन के क्षेत्र में ग्राहक उन्मुखी प्रशासन क्लाइंट ओरिएंटेड गवर्नेंस की धारणा सामने आती है जिसे हम विकास प्रशासन के नाम से भी जानते हैं । अतः बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन का स्वरूप पुलिस राज्य का ना होकर सहभागी शासन का है यह अब लोक कल्याणकारी राज्य से भी आगे जाकर विकास प्रशासन की स्थापना करता है । विकास प्रशासन के सफलता का समसामयिक प्रशासन में सबसे बड़ा दारोमदार ई गवर्नेंस पर है ।
कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली **Public Service distribution system** में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं । सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीक के कारण शासकीय नीतियो योजनाओ के क्रियान्वयन मे तेजी आई है । डायरेक्ट कैश डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ,क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र ,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आज की दुनिया में बहुत सामान्य है । करो का आनलाइन भुगतान, डायरेक्ट हितग्राही के खाते मे कैश भुगतान आदि सभी गवर्नेंस के कारण ही संभव है ।
इस प्रकार **e-governance** का अभिप्राय शासकीय विभागों और संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों तथा सेवाओं को पहुंचाना और उससे संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली तथा फीडबैक की समुचित व्यवस्था करना है ।

E-GOVERNMENT AND E- GOVERNANCE

ई-गवर्नमेन्ट और ई-गवर्नेन्स

इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः पर्यायवाची के रूप में किया जाता है लेकिन इन में थोड़ा अंतर है । विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नमेंट का संबंध शासकीय एजेंसियों के द्वारा सूचना तकनीकी के प्रयोग से सरकार के विभिन्न

अंगों संरचनाओं के द्वारा नागरिकों और व्यापार को सुविधाजनक बनाने सुविधाजनक बनाने से है । इसमे सरकार को पारदर्शी अनुक्रियाशील और उत्तरदाई बनाकर उसको रूपांतरित करने की क्षमता होती है ।
ई गवर्नमेंट शासन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है जिसकी पारदर्शिता जनता तक सुलभ हो या दूसरे शब्दों में एक गवर्नमेंट में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता की भागीदारी भी किसी हद तक सुनिश्चित की जाती है । ई-गवर्नमेंट सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करती है । जबकि ई गवर्नेंस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय बनाई गई योजनाओं के वितरण से संबंधित है उन योजनाओं का लाभ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक सहज सुलभ पारदर्शी तरीके से जनता तक वितरित करने में इसका प्रयोग किया जाता है । यह सूचना तकनीकि जैसे नेटवर्क इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल नेटवर्किंग आदि के प्रयोग के द्वारा शासकीय सेवाओं के पहुंच को सहज सुलभ त्वरित अनुक्रियाशील पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाती है ।
ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस भी कहा जाता है किंतु तकनीकी रूप से स्मार्ट का निश्चित अर्थ है जो ई गवर्नेंस का एक आवश्यक तत्व है । इसीलिए ई गवर्नेंस को संक्षेप में स्मार्ट गवर्नेंस का जाता है जिसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व है ।

संदर्भ

https://www.meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2672-e-governance.html